INTRODUCTION A

constitution is not only about the composition of the various organs of government and the relations among them. As we studied in the last chapter, the constitution is a document that sets limits on the powers of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights. In this chapter, we shall study the Fundamental Rights contained in the Indian Constitution. Part three of the Constitution of India lists the Fundamental Rights and also mentions the limits on these rights. In the past six decades, the scope of rights has changed and in some respects, expanded. After studying this chapter, you would know

- what are the various Fundamental Rights listed in the Constitution of India;
- how these rights are protected;
- what role the judiciary has played in protecting and interpreting these rights; and
- what is the difference between the Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy

- ❖भारतीय संविधान कौन–कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है
- ❖उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है
- ❖उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है और
- ❖मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है।

- **Fundamental Rights are different from other rights available to us. While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, Fundamental Rights are protected and guaranteed by the constitution of the country. Ordinary rights may be changed by the legislature by ordinary process of law making, but a fundamental right may only be changed by amending the Constitution itself**

❖मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। जहाँ साधरण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधरण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बना कर परिवर्तित कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों में परिर्वतन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता

Right to Equality

√ **Equality before law**

– **equal protection of laws**

√ **Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth**

– **equal access to shops, hotels, wells, tanks, bathing ghats, roads etc.**

√ **Equality of opportunity in public employment**

√ **Abolition of Untouchability**

√ **Abolition of titles**

समता का अधिकार

√ कानून के समक्ष समानता

– कानूनों के समान संरक्षण

√ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधर पर भेदभाव का निर्षध

– दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता

√ रोजगार में अवसर की समानता

√ छूआछूत का अंत

√ उपाधियों का अंत

Right to Freedom

√ **Protection of Right to**

– **freedom of speech and expression;**

– **assemble peacefully;**

– **form associations/unions;**

– **move freely throughout the territory of India;**

– **reside and settle in any part of India;**

– **practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.**

√ **Protection in respect of conviction for offences**

√ **Right to life and personal liberty**

√ **Right to education**

√ **Protection against arrest and detention in certain cases**

स्वतंत्राता का अधिकार

√ व्यक्तिगत स्वतंत्राता का अधिकार

– भाषण और अभिव्यक्ति का

– शांतिपूर्ण

– संगठित होने का

–भारत में कहीं भी आने–जाने का

– भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का

– कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का

√ अपराधें के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

√ जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्राता का अधिकार

√ शिक्षा का अधिकार

√ अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार

Right against Exploitation

√ **Prohibition of traffic in human beings and forced labour**

√ **Prohibition of employment of children in hazardous jobs**

शोषण के विरुद्ध अधिकार

√ मानव वेफ दुर्व्यापार और बंधुआ मशदूरी पर रोक

√ जोखिम वाले कामों में बच्चों से मशदूरी कराने पर रोक

Right to Freedom of Religion

- √ **Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion**
- √ **Freedom to manage religious affairs**
- √ **Freedom to pay taxes for promotion of any particular religion**
- √ **Freedom to attend religious instruction or worship in certain educational institutions**

धर्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

√ आस्था और प्रार्थना की आजादी

√ धर्मिक मामलों के प्रबंधन

√ किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता

√ कुछ शिक्षा संस्थाओं में धर्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता

Cultural and Educational Rights

√ **Protection of language, culture of minorities**

√ **Right of minorities to establish educational institutions**

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

√ अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार

√ अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार

Right to Constitutional Remedies

√ **Right to move the courts to issue directions/orders/writs for enforcement of rights**

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

√ मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार

Preventive detention

- **Ordinarily, a person would be arrested after he or she has reportedly committed some offence. However there are exceptions to this. Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the above mentioned procedure. This is known as preventive detention. It means that if the government feels that a person can be a threat to law and order or to the peace and security of the nation, it can detain or arrest that person. This preventive detention can be extended only for three months. After three months such a case is brought before an advisory board for review.**

निवारक नजरबंदी

➢सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो। पर इसके अपवाद भी हैं। कभी–कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिर गिंरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर–कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून–व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। तीन महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं।

- **Minorities are groups that have common language or religion and in a particular part of the country or in the country as a whole, they are outnumbered by some other social section. Such communities have a culture, language and a script of their own, and have the right to conserve and develop these.**

- अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है, ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है।

RIGHT TO CONSTITUTIONAL REMEDIES

- **One would agree that our Constitution contains a very impressive list of Fundamental Rights. But merely writing down a list of rights is not enough. There has to be a way through which they could be realised in practice and defended against any attack on these rights. Right to constitutional remedies is the means through which this is to be achieved. Dr. Ambedkar considered the right to constitutional remedies as 'heart and soul of the constitution'. It is so because this right gives a citizen the right to approach a High Court or the Supreme Court to get any of the fundamental rights restored in case of their violation. The Supreme Court and the High Courts can issue orders and give directives to the government for the enforcement of rights. The courts can issue various special orders known as writs.**

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

- इस बात से हर–कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है। लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके।'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉ. अंबेडकर ने इस अधिकार को 'संविधान का हृदय और आत्मा' की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं।

- **Habeas corpus: A writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it. It can also order to set free an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful or satisfactory.**

- बंदी प्रत्यक्षीकरण – बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ़्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ़्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक. हो, तो न्यायालय गिरफ़्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है।

- **Mandamus: This writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual**

- परमादेश – यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।

- **Prohibition: This writ is issued by a higher court (High Court or Supreme Court) when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction**

- निषेध आदेश – जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें ;उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालयद्ध उसे ऐसा करने से रोकने के लिए 'निषेध आदेश' जारी करती है।

- **Quo Warranto: If the court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, it issues the writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder.**

- अधिकार पृच्छा – जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय 'अधिकार पृच्छा आदेश' के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है।

- **Certiorari: Under this writ, the court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court.**

- उत्प्रेषण रिट – जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है।

What do the Directive Principles contain?

The chapter on Directive Principles lists mainly three things:

- **the goals and objectives that we as a society should adopt;**
- **certain rights that individuals should enjoy apart from the Fundamental Rights; and**
- **certain policies that the government should adopt.**

नीति–निर्देशक तत्वों की सूची में तीन प्रमुख बातें हैं

- वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए
- वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और
- वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

What do the Directive Principles contain?

You may get some idea of the vision of makers of our Constitution by looking at some of the Directive Principles shown below. The governments from time to time tried to give effect to some Directive Principles of State Policy. They passed several zamindari abolition bills, nationalised banks, enacted numerous factory laws, fixed minimum wages, cottage and small industries were promoted and provisions for reservation for the uplift of the scheduled castes and scheduled tribes were made. Such efforts to give effect to the Directive Principles include the right to education, formation of panchayati raj institutions all over the country, partial right to work under employment guarantee programme and the mid-day meal scheme etc.

नीति–निर्देशक तत्व क्या हैं?

नीति–निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधन निर्माताओं की 'भारत की कल्पना' का आभास होगा। समय – पर सरकार ने कुछ नीति–निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री–अधिनियम, न्यूनतम मश्जदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति–निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती–राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि समिलित हैं।

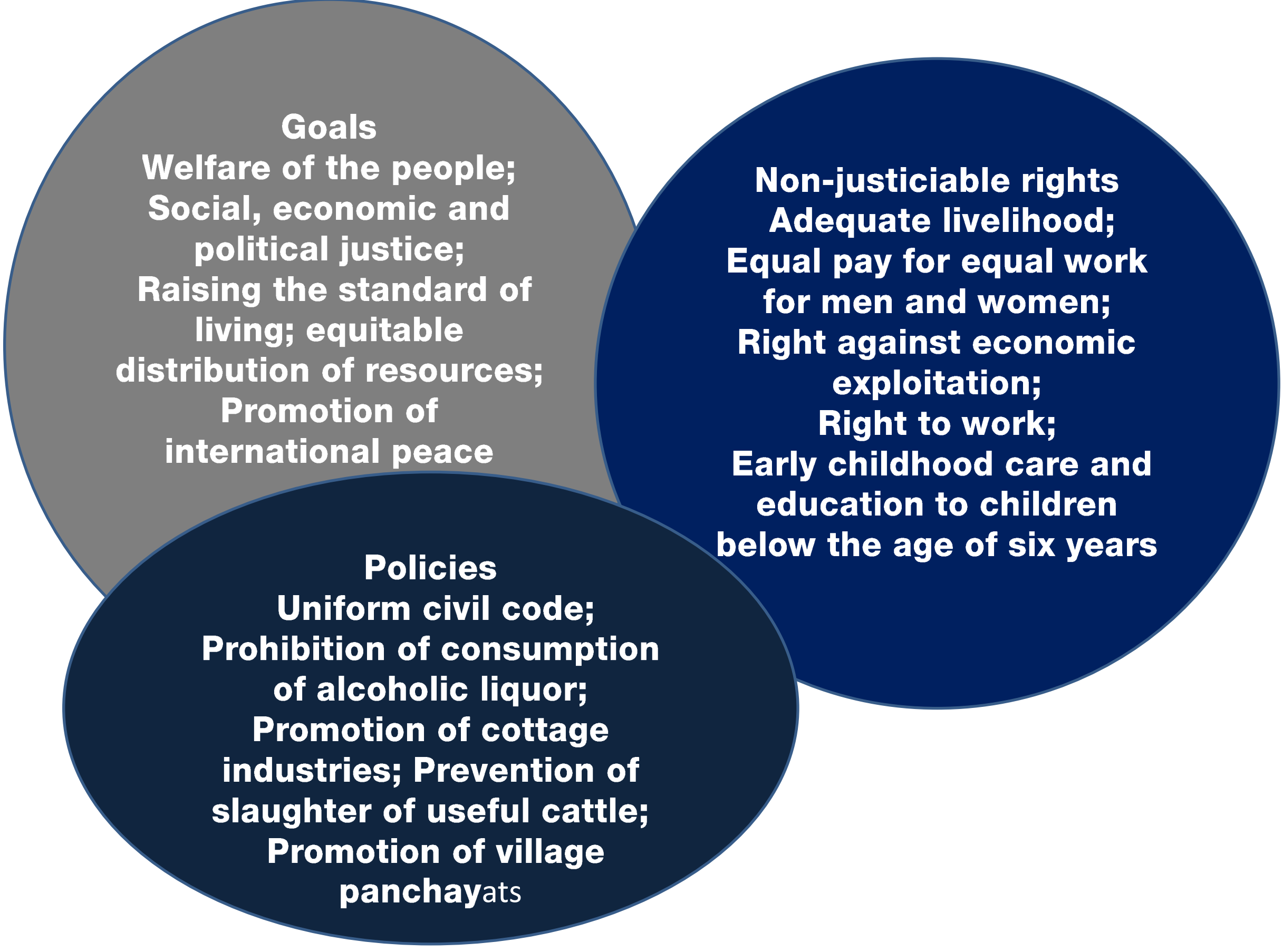

Goals
Welfare of the people;
Social, economic and political justice;
Raising the standard of living; equitable distribution of resources;
Promotion of international peace
Non-justiciable rights
Adequate livelihood;
Equal pay for equal work for men and women;
Right against economic exploitation;
Right to work;
Early childhood care and education to children below the age of six years
Policies
Uniform civil code;
Prohibition of consumption of alcoholic liquor;
Promotion of cottage industries; Prevention of slaughter of useful cattle;
Promotion of village panchayats

RELATIONSHIP BETWEEN FUNDAMENTAL RIGHTS AND DIRECTIVE PRINCIPLES

- **It is possible to see both Fundamental Rights and Directive Principles as complementary to each other. Fundamental Rights restrain the government from doing certain things while Directive Principles exhort the government to do certain things. Fundamental Rights mainly protect the rights of individuals while directive principles ensure the well-being of the entire society. However, at times, when government intends to implement Directive Principles of State Policy, it can come in conflict with the Fundamental Rights of the citizen. This problem arose when the government sought to pass laws to abolish zamindari system.**

These measures were opposed on the ground that they violated right to property. However, keeping in mind the societal needs that are greater than the individual interests, the government amended the Constitution to give effect to the Directive Principles of State Policy. This led to a long legal battle. The executive and the judiciary took different positions. The government claimed that rights can be abridged for giving effect to Directive Principles. This argument assumed that rights were a hindrance to welfare of the people. On the other hand, the court held the view that Fundamental Rights were so important and sacred that they cannot be limited even for purposes of implementing Directive Principles.

नीति–निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध

- मौलिक अधिकारों और नीति–निर्देशक तत्वों को एक–दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं वहीं नीति–निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति–निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी–कभी जब सरकार नीति–निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है, तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने शमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधर पर किया गया कि उससे संपत्ति कें मौलिक अधिकार का हनन होता है। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएँ वैयक्तिक हित से ऊपर हैं, सरकार ने नीति–निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई।

- कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति–निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धरणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति–निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

- **This generated another complicated debate. This related to the amendment of the Constitution. The government was saying that Parliament can amend any part of the Constitution. The court was saying that Parliament cannot make an amendment that violated Fundamental Rights. This controversy was settled by an important decision of the Supreme Court in Kesavananda Bharati case. In this case, the court said that there are certain basic features of the Constitution and these cannot be changed by Parliament. We shall discuss this in greater detail in Chapter 9 on 'Constitution as a Living Document'.**

- इसने एक और भी जटिल वाद–विवाद को जन्म दिया। वह संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानन्द भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधन की कुछ 'मूल–ढाँचागत' विशेषताएँ हैं और संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसे हम नवें अध्याय 'संविधान : एक जीवंत दस्तावेश' में विस्तार से पढ़ेंगे।